(ख) क्या विद्यमान पटौदी हाउस को गिराकर वहां एक सांस्कृतिक केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या पटौदी हाउस के निकट बने बैरकों और सर्वेंट क्वार्टरों को भी गिरा दिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) :(क) पटौदी हाउस में फर्नीचर तथा साजो-सामान की किसी स्टॉक की सूचना नहीं मिली है। दस्तावेजों के अनुसार प्रत्येक फर्नीचर साजो-सामान उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

Manufacture of isoproturon 50 per cent W.P. by M/s. Suraksha Chemicals and Engineers, Bombay

3765. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M/s. Suraksha Chemicals and Engineers, Bombay are manufacturing Isoproturon 50 per cent W.P. and are exclusively supplying to MRTP/Multinational Companies under the trade name of 'TOLKEN'; and

(b) if so, what is the source of technical materials, total quantity manufactured during the last 12 months and the names of the companies to whom this quantity was supplied and on what terms and conditions and the total gross profit earned by this company on Isoproturon, Fosetyl-AL, Bitertanol and other products supplied to multinational and other companies, product-wise and company-wise as on date?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) Messrs Suraksha Chemicals and Engineers, Bombay, have been granted registration for manufacture of Isoproturon 50 per cent W.P. under the Insecticides Act, 1968. Under this Act, there is no requirement for supply of such information by Companies and, therefore, this Ministry has no information on this subject.

Cadre review of Sectional Officers (Horticulture C.P.W.D.)

3766. SHRI KAPIL VERMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the cadre review of Sectional Officers (Horticulture, C.P.W.D.) has not been initiated so far; if so, by when the cadre review is likely to be taken up;

(b) what steps have been taken to expand the Horticulture Department;

(c) what is the present transfer policy in respect of Assistant Directors and Sectional Officers in the Directorate of Horticulture; and

(d) whether it is a fact that Sectional Officers and Junior Engineers are at par in terms of cadre and pay structure but not in terms of the facilities given to their counterpart Junior Engineers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) A working group has recently been set up by the DG(W), CPWD to compile data and formulate properly for cadre review of the cadres of J Es (Civil and Electrical) and Sectional Officers (Horticulture).

(b) The expansion of the Department of Horticulture depends upon the amount of work required to be executed. Recently, a study of the working of the various units of the CPWD was carried out by the National Productivity Council. The question of opening of additional divisions in the Dte. of Horticulture will

be examined, if found necessary, based on the recommendations of the National Productivity Council.

(c) Generally, and subject to exigencies of work, transfer out of Delhi is ordered on the basis of the length of stay Normally, officers are required to complete a tenure of three years at outstations.

(d) J Es (Civil and Electrical) and Sectional Officers (Horticulture) belong to different disciplines and, although the pay scales of the two categories have generally been equivalent, there are several significant differences in the recruitment rules, duties and responsibilities prescribed, respectively, for them.

रेपसीड तेल का आयात

3767. **श्री शिव कुमार मिश्र** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कितनी मात्रा मे रेपसीड तेल का आयात किया गया और इस के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई तथा किस-किस देश से इसका आयात किया गया ;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी-कितनी मात्रा मे रेपसीड तेल वितरित किया गया और उक्त अवधि के दौरान उनमे से प्रत्येक मे कितनी-कितनी राशि वसूल की गई ;

(ग) राज्य व्यापार निगम ने राज्य-सरकारो मे प्रशासनिक और सम्हलाई प्रभार के रूप मे प्रति टन कितनी राशि वसूल की ;

(घ) रेपसीड को इधर-उधर लाने जाने मे प्रति वर्ष कितने मूल्य की कितनी मात्रा का नुकसान हुआ ; और

(ङ) राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरूद्ध रेपसीड तेल का दुरूपयोग करने के सबंध मे कितनी शिकायते प्राप्त हुई है और इस संबध मे क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच॰के॰एल॰ भगत) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए अपरिष्कृत रेपसीड तेल की मात्रा तथा उसके मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है (इसमे आर॰ पी॰ ए॰ स्रोतों से किया गया कुछ आयात शामिल है) :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा (मी॰ टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1984–85	2,81,453	230.92
1985–86	1,66,098	128.29
1986–87	2,34,699	102.22

जिन देशों से विक्रेताओं द्वारा अपरिष्कृत रेपसीड तेल का पोत-लदान किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

कनाडा, पोलेड, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलेड, बेल्जियम, स्वीडन, फ्रांस, चीन तथा डेनमार्क ।

(ख और (ग) आयातित रेपसीड तेल के परिष्करण तथा उसे टीनों में बंद किए जाने के बाद राज्य व्यापार निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रो को गत तीन